

रजिस्ट्रे शन

डब्लू० / एन०पी०-91 / 2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 आश्विन 6, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गोपन अनुभाग-5

संख्या 330 / 83 / 10 / 07 / 2022-सी ० एक्स०-5 लखन ऊ , 28 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ०—4559(अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2022 के द्वारा विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37 वें) की धारा 3 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पापुलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया (पी०एफ०आई०) एवं सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (अारआईएफ), कैंपस फ्रन्ट ऑफ इंडिया (सीएफआई), आल इंडिया इमाम कांउसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रन्ट, जूनियर फ्रन्ट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फांउंडेशन, केरल सहित को "विधि विरूद्ध संगठन" घोषित किया गया है। यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए लागू होगी।

2—उक्त के साथ ही अधिसूचना सं0 का0आ0—4559 (अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2022 के आलोक में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर, 2022 द्वारा पूर्वोक्त विधि विरूद्ध संगठनों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (िनवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के अन्तर्गत प्रयोग की जानी वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्राधिकृत किया गया है।

3—उपरोक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त वर्णित प्रत्यायोजित शक्तियां ऐसी परिस्थितियों और शर्तों के अन्तर्गत, जैसा कि निर्देश में निर्धारित है, राज्य सरकार के अन्तर्गत समस्त पुलिस आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रे, टों द्वारा प्रयोग की जायेंगी।

4—अतः इस सम्बन्ध में एतद्द्वारा समस्त पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रे टों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का तद्नुसार प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

> आज्ञा से, संजय प्रसाद,

प्रमुख सचिव। पी०एस0यू०पी०—ए०पी० 561 राजपत्र—2022— (894)—588+25=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।